Demand to open more Medical Colleges/Nursing Training Institutes and another AIIMS in Bihar

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) : महोदय, कोविड महामारी के दौरान समूची दुनिया बेबस नज़र आई। इस आपदा ने मानव जीवन को पंगु बना दिया। हर आय वर्ग तथा हर आयु वर्ग के लोग इससे प्रभावित हुए। इस आपदा ने यह भी बताया कि हमें स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा इसके बुनियादी ढांचे के विकास पर और बल देने की जरूरत है। हमें उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को खड़ा करने की आवश्यकता है, जहाँ इसका नितांत अभाव है। सरकार ने अपनी ओर से तैयारी शुरू भी कर दी है तथा इस वर्ष के आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़े राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा आबादी के आनुपातिक घनत्व को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक एम्स भी खोले जाएंगे। यह भी कहा गया था कि प्रत्येक जिले में नर्सों की ट्रेनिंग के लिए संस्थान भी खोले जाएंगे।

महोदय, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जिला अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर तथा नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते सही उपचार नहीं मिल पाता है।

महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिहार में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को सबल बनाने के लिए प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों तथा नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को शीघ्रता से खोला जाए।

MR. CHAIRMAN: Shri Prasanta Nanda.

Demand to review parameters for Renewable Energy Purchase Obligation (REPO) for States like Odisha

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): In recent times, it is observed that Renewable Energy Purchase Obligation (REPO) is being raised every year irrespective of its availability in the concerned States. This poses a great problem for the States which are not endowed with renewable energy resources. It is learnt that REPO target of 41 per cent has been fixed for Odisha State by the year 2030. This target is too ambitious for the State of Odisha considering the fact that it has got limited potential for Solar RE as well as RE from small hydro sources. Renewable energy like wind, biomass is almost negligible in the State.

In fact, Odisha is considered as a State in terms of availability of renewable energy potential where projects such as solar power projects, hydel project can be implemented on commercial basis. Other renewable energy projects have lesser scope of implementation on commercial basis. Such naturally disadvantaged States, therefore, ought not to be penalised for not achieving stiff REPO targets.

As an alternative, it is suggested that States can comply with REPO target from